आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 04 (प्रति रविवार) इंदौर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

बेंगलुरु में आयकर के छापों में मिले 42 करोड़, अब राजनीति हुई शुरु

बेंगलुरु। आयकर की टीम ने बेंगलुरु के एक घर में छापेमार कार्रवाई की। आयकर विभाग को सूचना मिली थी पांच पांच सौ रुपए की गड्डियां भारी मात्रा में रखी गई है। जब टीम ने तलाशी ली तो बड़ी मशक्कत के 23 बॉक्सों में ये सभी गड्डियां मिली। कर्नाटक में कुछ ठेकेदारों और उनसे जुड़े लोगों के यहां से 42 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। छापे के बाद इस मामले पर राजनीति भी शुरु हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह रकम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ठेकेदारों से कमीशन के रूप में ली है। यह बहुत मामूली रकम है, जिसे आयकर विभाग ने पकड़ा है। यह सिर्फ नमूना है।

भाजपा नेता और एमएलसी एन रवि कुमार ने दावा किया कि ठेकेदार से वसूलीकर जमा की गई राशि में से जो आईटी ने पकड़ी है, वो 42 करोड़ रुपये हैं. इनमें 500 के नोट शामिल हैं, जिन्हें 23 बक्सों में रखा गया था। यह बातें भी सामने आ रही हैं कि ये कैश तेलंगाना चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कैश ठेकेदारों से लंबित 650 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए कमीशन के रूप में लिया गया था। रवि कुमार ने इस मामले की जांच की मांग की। कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। किसी ने भी किसी से पैसे नहीं मांगे. आरोप लगाने वालों के पास क्या सबूत है क्या भाजपा के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। हम भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और अन्य राज्यों में क्या हो रहा है। जहां भाजपा सत्ता में है, वहां कुछ नहीं होगा। जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां ऐसी चीजें होती हैं. ऐसे आरोप लगते हैं। इस मामले में तेलंगाना के मंत्री हरीश राव ने इस रकम को चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह पैसा बेंगलुरु के बिल्डरों, सोना व्यापारियों से कमीशन के रूप में इकट्ठा किया है, इसे तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भेजा जाना था, कांग्रेस ने 1500 करोड़ रुपये खर्च करना था. हरीश राव ने कहा कि आईटी टीम ने ठेकेदार अंबिकापति के यहां छापा मारा। अंबिकापति ने कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया था। आयकर अधिकारियों को छापे में 42 करोड़ रुपये कैश मिला है। बिस्तर के नीचे 23 बक्सों में 42 करोड़ रुपये के 500 रुपये के नोट रखे हुए थे। पहले 40 प्रतिशत कमीशन था, सरकार अब 50 प्रतिशत कमीशन ले रही है।

ठेकेदारों ने पल्ला झाड़ा

ठेकेदार के यहां हुई छापामार कार्रवाई पर कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने पल्ला झाड़ लिया है। संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना का कहना है कि ठेकेदार आठा साल से ठेकेदारी में शामिल नहीं था। उसके पास कृषि के साथ ही कई अन्य बिजनेस थे। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। बता दें कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच होने हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले हुई इस कार्रवाई से कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या ये पैसे तेलंगाना भेजे जाने थे, जहां महीने विधानसभा चुनाव होने हैं।

महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता केस में सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-

कोई स्पीकर को समझाए कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र स्पीकर पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें (स्पीकर राहुल नार्वेकर) समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्यवाही महज दिखावा नहीं हो सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। इस मामले में स्पीकर नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं, शिंदे गुट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें रखीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल (2024) में सितंबर-अक्टूबर में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साल जून के बाद से इस (विधायकों की अयोग्यता) मामले में कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी को स्पीकर को सलाह देने के लिए कहा है। यह भी कहा कि उन्हें (स्पीकर) मदद की जरूरत है।

पीएम मोदी ने की नागपट्टिनम व कांकेसंतुरई के बीच नौका सेवा की शुरुआत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेसंतुरई के बीच नौका सेवा शुरू की। इस मौके पर उन्होंने कहा, भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फेरी सेवा सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा, प्रगति और विकास के लिए साझेदारी भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने बताया कि कनेक्टिविटी के केंद्रीय विषय के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए संयुक्त रूप से एक विजन दस्तावेज अपनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी केवल दो शहरों को करीब लाने के

बारे में नहीं है। यह हमारे देशों को करीब, हमारे लोगों को करीब और हमारे दिलों को करीब लाती है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी व्यापार, पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ाती है, साथ ही दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करती है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका फिन-टेक और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। यह देखकर कि यूपीआई के कारण डिजिटल भुगतान भारत में एक जन आंदोलन और जीवन का एक तरीका बन गया है, पीएम ने बताया कि दोनों सरकारें फिन-टेक सेक्टर कनेक्टिविटी पर काम कर रही हैं। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिडों को जोड़ने पर भी चर्चा की क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा भारत और श्रीलंका दोनों की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने शनिवार को नौका सेवा के सफल शुभारंभ के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति, सरकार और श्रीलंका के लोगों का आभार व्यक्त कर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष निकाला, भारत अपने लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपादकीय

इंडिया गठबंधन का ओबीसी प्रेम

भारतीय जनता पार्टी ने 80:20 का जो खेल खेला था। उसका जवाब इंडिया गठबंधन को, अब भाजपा को देने का मौका मिल गया है। 80 फ़ीसदी हिंदुओं के वोट धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने की जो बयार बहाई थी। इसका फायदा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खुलकर मिला। धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर हिंदुत्व की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उसका जवाब अब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ओबीसी वर्ग के प्रति प्रेम जताकर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। बिहार में जाति आधार पर जनगणना हुई। 60 फ़ीसदी से ज्यादा पिछड़ी जातियां जनगणना की रिपोर्ट में सामने आई हैं। जिनमे अति गरीब, गरीब और मध्यवर्ग की बहुत बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षों से राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण बढ़ाने की मांग हो रही थी। कई राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 फ़ीसदी अधिकतम आरक्षण की सीलिंग तय किए जाने के कारण पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि कभी इनकी जनगणना हुई नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के आधार पर आंकड़े भी समय-समय पर मांगे हैं। केंद्र सरकार ने एक आयोग भी गठित किया था। जिसे पिछडा वर्ग की जनसंख्या कर रिपोर्ट सौंपनी थी। हाल ही में एक रिपोर्ट आयोग ने केंद्र सरकार को सौंप दी है। आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण के बारे में निर्णय करने की बात न्यायालय ने अपने निर्णयों में कई बार कही थी। बिहार सरकार ने जाति जनगणना करा ली है। इस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी। 60 फ़ीसदी से ज्यादा हिंदू जातियां बिहार में पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ऐसी स्थिति में अब विपक्ष और कांग्रेस के लिए 80-20 के धार्मिक ध्रुवीकरण की नई तोड मिल गई है। धार्मिक ध्रुवीकरण के मुकाबले में अब सामाजिक ध्रुवीकरण की नई लड़ाई भारत में शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाया है। उसके बाद से भारतवर्ष में सभी हिन्दू जातियों में अपने आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार को लेकर एक नई चेतना देखने को मिल रही है। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी जाति आधार पर एकजुट हो रहा है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से होता हुआ दिख रहा है। हिंदू समुदाय भी अब खंड-खंड में बंटने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाकर, महिलाओं का आरक्षण कानून बनाकर,महिलाओं का समर्थन पाने की चेष्टा की थी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुई दिख रही है। परिसीमन के बाद ही 2029 लोकसभा चुनाव मे महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है। भाजपा ने अभी से महिलाओं की उम्मीदें जगा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार महिलाओं को जाति आधार पर आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। यह माना जा रहा है,कि उच्च वर्ग की महिलाओँ को महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी की महिलाएं एक बार फिर पीछे रह जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, राहुल गांधी ने संसद के अंदर केंद्रीय सचिवालय में 90 सचिवों के बीच में से केवल 3 सदस्य पिछड़ा वर्ग के होने के बात कहकर सत्ता मे पिछड़े वर्ग की भागीदारी का नया मुद्दा, बना दिया है। एसटी,एससी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है। भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का जो धार्मिक ध्रुवीकरण बनाया था। उसी का जवाब सामाजिक ध्रुवीकरण के रूप में 20-80 का है। समय रहते भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के इस चक्रव्यूह को समझाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यदि इस चक्रव्यूह को भेद पाई, तो ठीक है। अन्यथा जाति समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा हैं।

इजरायल और हमास के युद्ध से मानवता पर बढ़ता खतरा

ललित गर्ग

रूस और यूक्रेन के बाद अब इजरायल और हमास के बीच धमासान युद्ध के काले बादल विश्व युद्ध की संभावनाओं को बल देते हुए लाखों लोगों के रोने-सिसकने एवं बर्बाद होने का सबब बन रहे हैं। युद्ध की बढ़ती मानसिकता विकसित मानव समाज पर कलंक का टीका है। हमास ने नासमझी दिखाते हुए आतंकी हमला करके सोये शेर को जगा दिया है। आतंकी हमले का पहला राउंड इस मायने में पूरा हुआ माना जा सकता है कि उसे अंजाम देने वाले संगठन हमास ने कहा है कि उसका जो मकसद था वह पूरा हो चुका है और अब वह युद्धविराम पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन प्रश्न है इजरायल इस हमले पर कैसे शांत रहेगा? उसके यहां हुए महाविनाश एवं व्यापक जनहानि के बाद उसके लिये कथित युद्धविराम प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है? इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा कि युद्ध शुरू तो हमास ने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। दुश्मनों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उन्हें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी।'' आज दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना प्रमुख प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इजरायल के साथ है। भारत युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला चाहता है, लेकिन कोई जबरन हिंसा एवं आतंक को पनपाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिये उचित कदम उठाने की होंगे।

हमास के सरगना मोहम्मद डेफ ने इस हमले को महान क्रांति का दिन बताते हुए कहा कि 'हमने इसरायल के विरुद्ध नया सैन्य मिशन शुरू किया है। बस अब बहुत हो गया। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे।' इस पर गुस्साए इजरायल ने भी आधिकारिक तौर पर 'हमास' के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करके इसे 'आप्रेशन आयरन स्वोर्ड्स' नाम दिया है तथा गाजापट्टी के इलाके में 17 ठिकानों पर इजरायल वायु सेना के लड़ाकू जैट विमानों द्वारा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जहां तक इजरायल की जवाबी कार्रवाई का सवाल है तो इतना तो तय है कि बात यहीं नहीं रुकेगी, जंग का दूसरा राउंड शायद पहले से ज्यादा भीषण एवं महाविनाशक होगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि नेतन्याहू सरकार इसे किस तरह से अंजाम देगी। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि गाजापट्टी उसके हमलों का निशाना बनेगी। गाजापट्टी में हमास का प्रभाव जरूर है, लेकिन वहां 23 लाख लोग रह रहे हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा हमास की गतिविधियों और योजनाओं से अनजान होगा। ऐसे बेकसूर लोग जितनी बड़ी संख्या में इजरायली कार्रवाई के शिकार होंगे, मानवाधिकार का सवाल उतने बड़े रूप में उभरेगा और फलस्तीनियों के लिए तथाकथित सहानुभूति भी जुट सकती है।

विश्व शांति, अमन एवं अहिंसक समाज रचना दुनिया की जरूरत है, लेकिन हमास जैसी आतंकी सोच इसकी सबसे बड़ी बाधा है, इसलिये हमास की जितनी निंदा की जाए कम है। जिस संगठन को बंदूक छोड़कर गाजा पट्टी के विकास में लगना चाहिए, वह संगठन धर्म-अधर्म के रास्ते ताकत सिर्फ इसलिए जुटाता है, ताकि इजरायल के शरीर पर पहले से कहीं गहरा छुरा धंसा सके, मर्माहत आघात कर सके? मोसाद बनाम हमास की लड़ाई मानो एक व्यवसाय बन गई है, विकृत एवं हिंसक मानसिकता का स्थायी घर बन चुकी है। दोनों देशों की सत्ताएं आखिर शांति एवं अमन का सबक क्यों नहीं लेती? स्वयं अपने देश में स्थायी शांति के प्रति गंभीर क्यों नहीं होती है? आज उन्हें स्थायी शांति के उपायों पर जोर देना चाहिए, दुनिया को ऐसे देशों की जरूरत है, जो आतंकमुक्ति को सही दिशा में प्रेरित करें, ताकि पश्चिम एशिया के खूनी दलदल को हमेशा के लिए पाटा जा सके।

अभी लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला के कुछ हमले हुए हैं लेकिन लेबनान सरकार उस इलाके में शांति और स्थिरता बने रहने की इच्छा जताने तक सीमित है। ईरान और सऊदी अरब ने भी फलस्तीनियों के हक में शांति कायम करने की कोशिश की बात कही है। अगर बात बढ़ी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमास के लिए समर्थन बढ़ा तो हालात बदतर ही होंगे। दुनिया को लगातार युद्ध, आतंक, अशांति, हिंसा की ओर धकेलने वालों से सवाल पूछना ही होगा कि युद्ध एवं आतंक से हासिल क्या होगा? सबसे पहले धर्मगुरुओं से और उसके बाद राजनीतिक आकाओं से यह समझना होगा कि ऐसी युद्ध एवं आतंक की मानसिकता से किसका भला हो रहा है? निर्दोषों की हत्याएं भला कैसे जायज हैं? अगर ऐसी हत्याएं जायज हैं, तो फिर मजहबों के मानवीय एवं शांतिप्रिय होने का बखान बंद होना चाहिए। बुरा आदमी और बुरा हो जाता है जब वह साधु बनने का स्वांग रचता है। दुनिया में छोटी-छोटी बातों पर लोगों के दिल आहत हो जाते हैं, पर हजारों निर्दोष एवं मासूक बच्चों एवं महिलाओं की मौत से कौन आहत हुआ है? कहां है मानवता? कहां है विश्वशांति का स्वप्न? निश्चित ही हिंसा की धरती पर शांति की पौध नहीं उगायी जा सकती।

लगभग सत्तर साल से फलस्तीन के नाम पर जो खून-खराबा हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन इलाकों में दुश्मनियों को इंसानी रगों में पाला जाता है, ताकि मौका आने पर खून बहाया जा सके? क्या ऐसे इलाकों में युवा जवान ही इसलिए होते हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर सकें? कोई ऐसे दाग-धब्बों के साथ अपने देश का इतिहास लिखता है क्या? बड़ा प्रश्न है कि इस व्यापक हिंसा एवं आतंक को रोकने वाला कौन होगा? कोई आतंकी हमास के साथ दिख रहा है, तो कोई इजरायल के लिए लुट-मिट जाने को बेताब है? बात हर तरफ विनाश की है। युद्ध एवं आतंक करने वाले और उनको प्रोत्साहन देने किसी को भी आज तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं मिला, जो उसे गौरवान्वित कर सका हो। जब तक आतंक एवं युद्ध की मानसिकता वाले राष्ट्रों के अहंकार का विसर्जन नहीं होता तब तक युद्ध की संभावनाएं मैदानों में, समुद्रों में, आकाश में भले ही बन्द हो जाये, दिमागों में बन्द नहीं होती। इसलिये आवश्यकता इस बात की भी है कि कि जंग अब विश्व में नहीं, हथियारों में लगे, आतंक एवं हिंसक मानसिकता पर लगे। मंगल कामना है कि अब मनुष्य यंत्र के बल पर नहीं, भावना, विकास और प्रेम के बल पर जीए और जीते।

इस हिंसक, आतंकी एवं युद्ध के दौर का दुखद पहलू है कि पुतिन का नया रूस भी यूक्रेन को निशाना बनाते हुए बच्चों एवं महिलाओं को नहीं बख्शता है। जहां अपने और पड़ोसी के कल्याण की चिंता होनी चाहिए थी, वहां केवल बदले की भावना हावी है। बर्बरता, क्रूरता, उन्माद एवं जघन्यता बढ़ती जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उग्रवादी समूह को मलबे में फेंक देने की कसम खाई है। निर्ममता एवं बर्बरता की पराकाष्ठा कर रहे आतंकियों की जगह मलबे में ही है, पर उन मासूम बच्चों, औरतों और आदमियों का क्या दोष, जो कहीं से भी आतंकी नहीं हैं, मगर निशाना बन रहे हैं? क्या मानव सभ्यता में आंतकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई दोषी और निर्दोष के बीच भेद किये बिना सफल हो सकती है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी को हर समय विनाश की संभावनाओं पर कायम रखने जैसा है। ऐसे युद्ध का होना विजेता एवं विजित दोनों ही राष्ट्रों को सदियों तक पीछे धकेल देगा, इससे भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने का भी बड़ा कारण बनता है। युद्ध एवं विनाश की सघन होती स्थितियों के बीच उल्लेखनीय है कि इसरायल ने 1970 में ईराक द्वारा फ्रांस से खरीदे परमाणु प्लांट पर 1 मिनट 20 सैकेंड में 16 बम गिरा कर परमाणु प्लांट नष्ट करने में सफलता पाई थी। कहना मुश्किल है कि इस घटनाक्रम का अंजाम क्या होगा, फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी यह विवाद सुलझ सके उतना ही दुनिया के लिए अच्छा होगा। पहले ही विश्व शांति खतरे में पड़ी हुई है, अब 'हमास' व इसरायल युद्ध ने यह खतरा और बढ़ा दिया है तथा अतीत में हो चुके दो विश्व युद्धों के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेजी से सुनाई दे रही है। युद्ध विराम के साथ अभय का वातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव जरूरी है। मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति देनी होगी, स्वयं अभय बनकर विश्व को निर्भय बनाना होगा। इसी से किसी एक देश या दूसरे देश की जीत नहीं बल्कि समूची मानव-जाति की जीत होगी।

मुआवजा नहीं मिलने से अटका राऊ सर्कल फ्लाईओवर का काम

डेढ़ साल में सिर्फ 50 फीसदी काम हुआ, अब नई डेडलाइन मार्च 2024 की, जाम से रोजाना हो रही परेशानी

इंदौर। राऊ सर्कल पर 44 करोड़ की लागत बन रहे फ्लाई ओवर का काम 31 अगस्त की डेडलाइन निकलने के बावजूद अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। जिसका खामियाजा हाईवे से निकलने वाले वाहन चालकों के अलावा स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों को उठाना पड़ रहा है। ब्रिज का एक हिस्सा इंदौर-देवास बाइपास तो दूसरा महू-खलघाट (मुंबई) रोड की ओर प्रस्तावित है। मुंबई की ओर जाने वाले छोर पर एक निजी जमीन मालिक मुआवजा ना मिलने के कारण कई महीने से काम नहीं होने दे रहा है। इसके चलते ब्रिज के एक हिस्से का काम पूरी तरह से बंद है।

राऊ सर्कल से होकर रोजाना मुंबई और आगरा की तरफ हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। वहीं इस सर्कल से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही इंदौर से आने-जाने वाले वाहन भी बड़ी संख्या में निकलते हैं। ब्रिज निर्माण के कारण चौराहे पर आए दिन जाम लगा रहता है।

2 जून 2022 को शुरू हुआ था काम-एनएचआई ने ब्रिज का ठेका 8 अप्रैल 2022 को मेसर्स विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 जून 2022 से भी काम भी शुरू कर दिया, लेकिन एक साल चार महीने बाद भी ब्रिज का 40त्न भी काम नहीं हो सका है। बता दें कि कंपनी ने 2 जून 2022 को ड्राइंग का काम शुरू किया था। वहीं इसके पहले 25 मार्च 2022 को कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किया गया था। जिसके एग्रीमेंट की प्रकिया एक माह में पूरी कर ली गई थी।

फिर एनएचआई ने कम्पनी को दी दूसरी डेड लाइन-धीमी गति से कम होने के कारण निर्धारित समय सीमा पर विंध्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी ओवरब्रिज

का काम पूरा नही कर पाई। इस पर कम्पनी ने कई समस्याओं का हवाला देते हुए एनएचआई से मार्च 2024 तक काम की डेडलाइन ले ली है। कम्पनी के अधिकारियों का कहना है की अगर मुआवजे वाला विषय जल्दी सुलझ जाता है तो हम मार्च तक प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लेंगे।

अब जन लीजिए कि ओवरब्रिज के काम में क्यों हो रही है देरी-विंध्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर नरेंद्र मिश्रा के मुताबिक मुंबई रोड पर लगभग 0.045 हेक्टेयर जमीन राजेंद्र अरोरा नामक व्यक्ति की है। उन्होंने आपत्ति ली है कि की पूर्व में किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके द्वारा निजी भूमि पर तार फेंसिंग कर काम रोक दिया गया है। जिसकी जानकारी हमारे द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआइ) को से दी गई है। जिस पर एनएचआई द्वारा उक्त व्यक्ति को मुआवजा दिए जाएगा। एनएचआइ अफसरों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर निराकरण करने को कहा है। अब अरोरा की जमीन का अधिग्रहण आपसी सहमति से किया जा रहा है। मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होते ही हम इस ओर भी तेजी से काम शुरू करेंगे।

31 अगस्त 2023 को पूरा हो जाना चाहिए था ओवरब्रिज का काम-राऊ सर्कल पर बन रहे इस ब्रिज के लिए एनएचआई के द्वारा 31 अगस्त-2023 की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन काम धीमी गति होने के कारण आधा भी नहीं हो सका। दोनों तरफ 925-925 मीटर लंबी दो सर्विस रोड भी बनाई जानी हैं। लेकिन अभी तक मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर सिर्फ ट्रैफिक डायवर्जन के लिहाज से सर्विस रोड ही नहीं बन पाई है। उसके बाद से इस ओर का पूरा काम रुका पड़ा है। वहीं देवास की ओर दो पिलर खड़े कर स्लैब डालने की तैयारी की जारी है। फिलहाल मध्य भाग में बनाए गए पिलर पर एक स्लैब डालने का काम पूरा किया जा चुका है।

राऊ सर्कल पर आए दिन लगने वाले जाम और हादसों को रोकने के मद्देनजर इस फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि इसके बनने से इंदौर को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। लेकिन पिछले डेढ़ साल से ब्रिज का काम शुरू होने के बाद से सर्कल पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां से गुजरने वाले वाहनों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार लम्बे जाम के करण विवाद की स्थिति भी बन जाती है।

IIM इंदौर करेगा सर्कल का सौंदर्यीकरण

राऊ सर्कल का सौंदर्यीकरण आईआईएम इंदौर द्वारा किया जाएगा। आईआईएम द्वारा पिछले साल इसे लेकर घोषणा की गई थी। आईआईएम इस चौराहे की रोटरी और लैंडस्कैप को अत्याधुनिक तरीके से डेवलप करेगा। यहां फ्लाई ओवर ब्रिज के कारण सर्कल को छोटा किया जाएगा और वहां ढ्ढह्रू का मॉडल लगाया जाएगा। इसके आसपास सौंदर्यीकरण होगा और यह चौराहा अपने आप में सबसे अलग होगा। लोग यहां बैठ भी सकेंगे। प्लानिंग कुछ ऐसी रहेगी कि आवागमन भी बाधित नहीं होगा।

इमरजेंसी में एम्बुलेंस के सिस्टम पर भी काम

राऊ सर्कल के निर्माण में पांच मुख्य सूत्र होंगे। यानी ट्रैफिक एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी व एन्वायर्नमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इमरजेंसी के तहत ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था होगी कि अगर भीड़ में एम्बुलेंस के लिए रास्ता चाहिए तो क्या सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए काम होगा। कुल मिलाकर फ्लाई ओवर व सर्कल दोनों के बन जाने के बाद यहां का नजारा ही कुछ और होगा।

कर्मचारी लगे निर्वाचन ड्यूटी में, समय पर नहीं घोषित हो सकेंगे रिजल्ट

डीएवीवी अधिकारी कर रहे ड्यूटी कैंसिल करवाने की कोशिश

इंदौर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के परीक्षा, गोपनीय और अन्य विभागों के अधिकांश कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनावों में लगी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के रिजल्ट समय पर नहीं घोषित हो सकेंगे। इसका असर आने वाली परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। करीब 70 हजार छात्रों को 30 अक्टूबर तक उनका प्रमोशन करना है। इनके रिजल्ट पर भी संशय है। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। निर्वाचन कार्य में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 350 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। इनमें परीक्षा, गोपनीय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या ही 100 के आसपास है। इसके अलावा डीएवीवी के विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिकारी-कर्मचारी अलग हैं। इसके चलते विवि में परीक्षा, रिजल्ट से जुड़ा काम प्रभावित होना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव संबंधी कामो में लगी है। इसके कारण आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा प्रभावित होंगी। विवि के अधिकारी कुलपति के माध्यम से कुछ कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितने कर्मचारियों की ड्यूटी निरस्त होती है इसका निर्णय तो निर्वाचन अधिकारी को लेना है। कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी निरस्त हुई है, लेकिन अब भी कई कर्मचारी चुनाव संबंधी काम कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अशेष तिवारी ने बताया कि 70 प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी आचार संहिता लगते ही लग गई है। इसका असर परीक्षाओं के साथ ही परिणामों पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में कुछ कक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी होने को था, लेकिन अब यह जारी नहीं हो सकता। कर्मचारी ही नहीं है परीक्षा विभाग में इसके साथ ही आने वाले दिनों में रिजल्ट घोषित होना है। अब परीक्षा और परिणाम दोनों ही कुछ डिले होंगे। कुलपति के माध्यम से प्रयास किए जा रहे है कि परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए।

संवेदना और पीड़ा से जन्मता हैं साहित्य-जोशी

इंदौर। जब हम किसी कार्य को मन लगाकर करते है और उसी में पूरी तरह से खो जाते हैं तो यह एक तरह का ध्यान है। स्वयं को पहचानना और कनेक्ट हो जाना भी अध्यात्म है। जब हम परमात्मा के प्रति शरणागत हो जाते तो वही हमारी रक्षा अवश्य करता है। ये विचार अध्यात्म के क्षेत्र में वर्षो से काम कर रही लेखिका और विचारक डॉ. मनीषा अनवेकर के है, जो उन्होंने मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, राउ में आयोजित दो दिवसीय लिट्रेचर फेस्टिवल के समापन अवसर पर कहे। आयोजन द ग्रेट इंडियन बुक टूर जयपुर ने किया था। डॉ. मनीषा हर महीने एक पुस्तक लिखती है और अभी तक उनकी 73 किताबें प्रकाशित हो चुकी जिसमें अधिकाश अध्यात्म पर है। यह जानकारी प्रशांत गुप्ता ने दी। सत्र की शुरुआत शहर की लेखिका रिचा चतुर्वेदी की पुस्तक इंस्टेंट सोल इंपावर्मेंट पर चर्चा से हुई। जिसमें लेखिका ने कहा कि बेहतर से बेहतर बनने की यात्रा हम आज से भी शुरू कर सकते है, मतलब जब जागे तभी सबेरा।और हमारे जो डाउट हैं,डर है , कमियाँ है और कुछ दूसरी भी समस्यायें है तो इस पुस्तक को पढ़कर उससे निजात पा सकते है। बच्चों को बेहतर बनाने के लिए अभिभावक अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वे अभिभावक के अधूरे सपने को साकार करे। महू इंदौर की लेखिका समृध्दि जैन ने अपनी पुस्तक द पर्पल एनवलप के बारे में बताया कि छोटी उम्र से लेखन कर रही हुॅ ,लेकिन उसे कभी गंभीरता से पब्लिश नही कराया। अब इस दिशा में काम कर रही हूं। पहली पुस्तक का अच्छा रिस्पांस मिला और अब दूसरी की तैयारी हुँ।

भाजपा ने मंडला में कांग्रेस महासचिव द्वारा की गई स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप की गारंटी के असर का शुरू करवाया आकलन

मिशन 2023: शिवराज की महीनों की घोषणाओं पर प्रियंका गांधी के मास्टर स्टोक ने बदला मप्र का चुनावी माहौल

57,000 करोड़ पर भारी 7500 करोड़!

भाजपा में शुरू हुआ

भोपाल । मप्र में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों का प्रचार जोर पकडने लगा है। खासकर भाजपा और कांग्रेस में सत्ता की जंग हो रही है। इसके लिए रोज नई घोषणाएं और दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकार बनाने के इरादे से एक और बड़ा दांव चला है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मंडला की सभा में पढ़ो और पढ़ाओ योजना लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के लिए करीब 7500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की जरूरत होगी। दरअसल, कांग्रेस ने स्कूली विद्यार्थियों के जरिए उनके वोटर माता-पिता व अन्य वयस्क परिजनों को साधने का प्रयास किया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की घोषणा का प्रदेशभर में बड़ा प्रभाव पड़ा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिवराज की 57,000 करोड़ की घोषणाओं पर प्रियंका की 7500 करोड़ की घोषणा भारी पड़ सकती है।

गौरतलब है कि मंडला में प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढने वाले बच्चों को 500 रुपये से 1500 रुपये तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस घोषणा के बाद अमर उजाला ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढने वाले बच्चों की मौजूदा संख्या के आधार पर स्कॉलरशिप पर खर्च होने वाली राशि की गणना। इसके अनुसार सरकार को हर साल करीब 7,428 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। स्कूल शिक्षा विभाग का पिछला बजट 36 हजार करोड़ रुपये का है। इसमें 80 प्रतिशत राशि वेतन और अन्य मदों में खर्च हो जाती है। मप्र सहित देशभर में यह परंपरा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि चार साल सरकार में रहने के बाद भी चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर देती हैं। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। आज यह रेवड़ी कल्चर चुनावी परंपरा बन गई है। यही वजह है कि मप्र में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की घोषणाओं की भरमार कर दी है। खासकर भाजपा सरकार की घोषणाएं चर्चा में है। चुनावी साल में हुईं घोषणाएं सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही हैं। गौरतलब है कि मप्र सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है और खर्च इससे 54 हजार करोड़ ज्यादा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 57 हजार करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं। अकेले लाड़ली बहना योजना पर ही सालाना 19 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

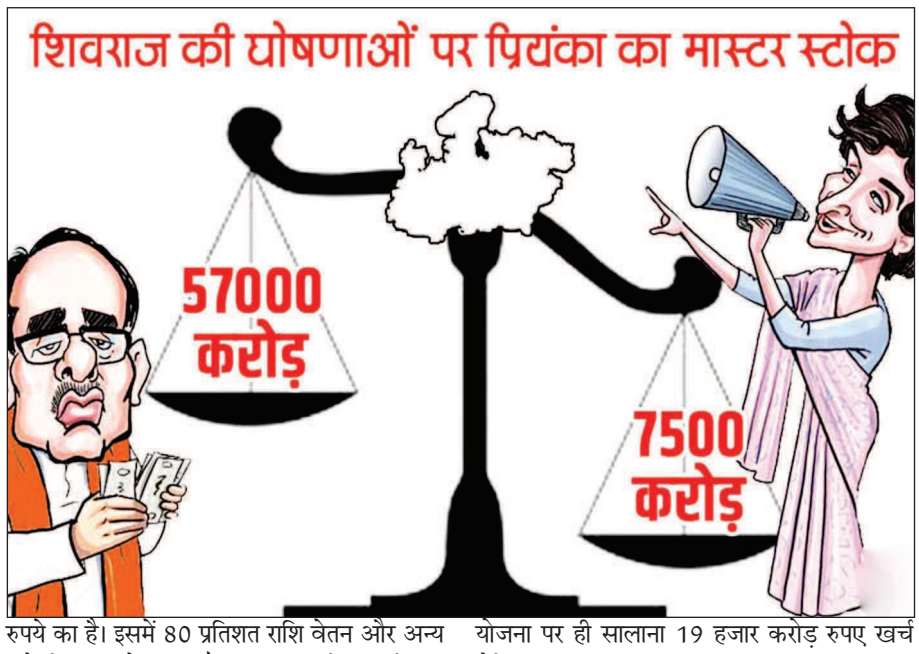

90 लाख घरों पर असर

जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी की एक घोषणा ने 90 लाख घरों पर असर पड़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पहलीं से 12वीं तक की कक्षा में 89 लाख 85 हजार 543 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इसमें पहली से आठवीं तक की कक्षा में 65 लाख 63 हजार 745 बच्चे रजिस्टर्ड है। इन बच्चों को कांग्रेस की 500 रुपये देने की घोषणा के अनुसार एक माह 328.18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं, नौंवी से 10वीं तक की कक्षा में 14 लाख 48 हजार 881 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इनको 1 हजार रुपये देने पर 144.89 करोड़ रुपये प्रतिमाह का खर्च आएगा। वहीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के 9 लाख 72 हजार 917 बच्चों को 1500 रुपये देने पर 145.94 करोड़ रुपये प्रतिमाह का खर्चा आएगा। यानी कुल 7 हजार 428 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा।

लाडली बहना और नारी सम्मान योजना

प्रदेश की शिवराज सरकार लाडली बहना योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। यदि 1.25 करोड़ लाडली बहना योजना में 1250 रुपये प्रति माह सरकार देती है तो 18 हजार 750 रुपये सालाना खर्च बनता है। वहीं, यदि इतनी ही महिलाओं को नारी सम्मान के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है तो करीब 22 हजार 800 करोड़ रुपये साल का खर्चा आएगा।

अभी बच्चों को यह मिल रही सुविधा

स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में पहली से पांचवी तक के बच्चों को 600 रुपये ड्रेस के और किताबें निःशुल्क देता है। इन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। वहीं, छठी के बच्चों को 300 रुपये और सातवीं एवं आठवीं के बच्चों को 400 रुपये स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है। साथ ही 600 रुपए ड्रेस के लिए अलग से दिए जाते है। नौंवी से 10वीं तक के बच्चों को एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग अनुसार तय छात्रवृत्ति अनुसार साल में दो हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा किताबें भी मुफ्त दी जाती है। वहीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को एससी, एसटी ओर ओबीसी वर्ग अनुसार करीब 3000 रुपये तक सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही किताबें मुफ्त दी जाती हैं। प्रदेश सरकार लाडली बहनों और उज्जवला योजना के हितग्राहियों को 450 रुपये में गैस सिलिंडर दे रही है। वहीं, कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर हर परिवार को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने का वादा किया है।

शिवराज सरकार नौकरियां देने में रही विफल-शोभा ओझा

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा के पिछले 18 वर्षों के शासन में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया है। भाजपा सरकार बेरोजगारों को नौकरियां देने में भी असफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहां दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा के पिछले 18 वर्षों के शासन में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया है। कांग्रेस ने शनिवार को बेरोजगारी को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और कथित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण नौकरियां देने में विफल रहने का आरोप लगाया। शोभा ओझा का आरोप है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजनों में करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च करने के बावजूद राज्य में निवेश के नाम पर कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट नौकरियों से भी वंचित रहे। यह शर्मनाक है कि राज्य में 17 हजार छात्र और बेरोजगार लोग आत्महत्या कर चुके हैं।

भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले किए हैं। पिछले 18 वर्षों में भारी बेरोजगारी, छात्र आत्महत्याओं और घोटालों का शर्मनाक दौर देखने को मिला है। उन्होंने आरोप लग्राया कि भाजपा के संरक्षण में प्रदेश में तमाम माफिया पनपते रहे, जिससे सरकारी नौकरियां घोटालों की भेंट चढ़ गईं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति खराब है। राज्य के 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। इतना ही नहीं स्कूली शिक्षा की स्थिति भी काफी दयनीय है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 2600 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। 50 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। उन्होंने घोटाले गिनाते हुए कहा घोटालों की एक पूरी श्रृंखला है। जैसे- व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला आदि। कांग्रेस युवाओं के भविष्य को लेकर प्रदेश में बेहद संवेदनशील है। यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आई तो घोटालों में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा।

18 साल का ठगराज– शिवराज–सुरेन्द्र राजपूत

भोपाल। अभा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रोज सोचता हूं कि मप्र के 18 साल के शिवराज शासनकाल का कोई तो अच्छा काम होगा, जिस विषय मैं आप साथियों से वार्ता करूंगा। पर मैं हर रोज गलत साबित हो जाता हूं। हर रोज शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार खबर की शक्ल में सामने आ जाता है। आज आदिम जाति कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आ गया, जिसमें 10 करोड़ रू. का घोटाला हुआ है, जिसमें 7 साल से सह-आयुक्त रहे आठ अफसरों पर न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि नियम विरूद्व उन्होंने खाते से ही आहरण राशि जारी रखी। क्या मुख्यमंत्री शिवराज का सभी तरह के भ्रष्टाचारियों को सरंक्षण प्राप्त है कि अधिकारी खुलेआम नियम विरूद्व खाता खोलते थे और उससे राशि खुदी राशि निकालते थे। शिवराज ये पैसा किसको जाता था। कहीं ये पैसा सिंधिया वाले गद्दारों को खरीदने के काम तो नहीं आता था। शिवराज आपके शासन में तो आदिवासियों पर अत्याचार की और आदिवासी विभाग में अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है। विदित है कि मप्र में सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोग अनादिकाल से रह रहे हैं, किंतु पिछले 18 सालों की शिवराज सरकार में विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना और आत्मा को छलनी करने वाले कुकृत्यों के शिकार हैं और शिवराज सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सत्ता के नशे में मदमस्त भाजपा नेताओं ने आदिवासी समाज के खिलाफ नशपिशाची कृत्यों की सारी हदें पार कर दी हैं।

प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा

पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस को तो आतंकियों को बचाना है

भोपाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एक बात आज तक समझ में नहीं आई। वो जब अपनों पर चोट होती है, तो दर्द से तिलमिला जाते हैं। लेकिन हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर बर्बर हमला किया, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब इजराइल ने जवाब देना शुरू किया, गाजा पट्टी को तहस-नहस करना शुरू किया, तो दिग्विजय सिंह की नींद उड़ गई। कांग्रेस के लोग शोर मचाने लगे हैं। कोई फिलिस्तीनियों की जानमाल की चिंता कर रहा है, तो किसी को मानव अधिकार दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ 97 परसेंट केस झूठे हैं। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन हो, उसमें दिग्विजय सिंह कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं? पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का असली काम तो आतंकियों को बचाना है। ये लोग आतंकियों से प्रेम करते हैं, तुष्टिकरण से प्रेम करते हैं और इनका असली गेम यही है। कुख्यात आतंकी संगठन हमास से सहानुभूति रखने वाले ये लोग देश का साथ क्यों देंगे? यह बात प्रदेश के गृहमंत्री मिश्रा शुक्रवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजयसिंह के बयान से सहमत है? सोनिया गांधी से मेरा सवाल है कि ऐसे भारत विरोधी लोग आपकी पार्टी में क्यों हैं? राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि मि. बंटाढार जैसे लोग उनकी मोहब्बत की दुकान के मैनेजर क्यों हैं? प्रियंका जी कल मध्यप्रदेश आकर झूठ बोल रही थीं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर मौन साध रखा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो बड़े भाई-छोटे भाई हैं, फिर कमलनाथ जी क्यों खामोश हैं? उन्हें भी यह बताना चाहिए कि क्या वे दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तफाक रखते हैं ? मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की चालबाजी चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता पर विश्वास रखती है, तो उसे दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलना दिग्विजय सिंह का स्वभाव बन गया है। हाल ही में एक कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस बारे में दिग्विजय सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा है कि ये आतंकवादियों के बाप हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सनातन संस्कृति पर आक्रमण करने

वालों की फ्रंटलाइन में रहते हैं। ये भगवा आतंक की बात करते हैं, महाकाल लोक पर सवाल उठाते हैं, राम जन्मभूमि पर सवाल उठाते हैं, किसी दूसरे धर्म पर नहीं। ये पूछते हैं कि गाय कैसे माता हो सकती है? लेकिन बकरी पर कभी सवाल नहीं उठाते। जाकिर नाइक इनके लिए शांतिदूत है और वैश्विक आतंकी ओसामा बिन लादेन को ये ओसामा जी कहते हैं। ये बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के यहां आंसू बहाने सोनिया मैडम को ले जाते हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि भोपाल जेल से जब सिमी के आतंकी भागे, तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। इन्हें उज्जैन में लगने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 'काजी जी जिंदाबाद' सुनाई देते हैं। ये कह रहे हैं कि नूह जैसे दंगे मध्यप्रदेश में भी होंगे। इनका बस एक ही काम है कि मुस्लिमों को डराओ, हिंदुओं को बांटो और दंगे कराओ। इन्होंने एक फर्जी फोटो को खरगोन की मस्जिद का फोटो बताकर पोस्ट कर दिया था।

दोमुंही राजनीति करती है कांग्रेस

डॉ. मिश्रा ने कहा कि 'कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है मातम भी मनाना है।' यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस दोमुंही राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं, जो यह कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो कश्मीर में धारा 370 बहाल कर दी जाएगी। कश्मीर में आज स्थिति सामान्य हो चुकी है और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आ रहे हैं। लेकिन ये कश्मीर में 370 वापस लाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह उसके 97 प्रतिशत लोगों को बेकसूर बता रहे हैं। ये किस आधार पर क्लीनचिट दे रहे हैं, वो नहीं बताते। क्या ये इस मामले से जुड़ी जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या यह न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये सिमी की तुलना बजरंगदल से करते हैं। कहां एक राष्ट्रवादी संगठन और कहां सिमी के राष्ट्रविरोधी लोग।

- कांग्रेस की सरकारों में ही होता है कन्हैया का सिर तन से जुदा

डॉ. मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय प्रदेश में सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झिरन्या के जंगलों में कुएं में भरे हुए हथियार मिले थे। जहां कांग्रेस या घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकारें हैं, वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। वहीं, कन्हैया का सिर तन से जुदा होता है, क्योंकि ये आतंकियों को प्रश्रय देते हैं। लेकिन जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि मध्यप्रदेश या उत्तरप्रदेश में ऐसा काम कर सके। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि किसी मुस्लिम देश ने हमास का समर्थन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर यह कल्पना की जा सकती है कि अगर ये सत्ता में आ गए, तो किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज जातीय जनगणना को लेकर जो बातें कर रही है, वह भी हिदुओं को बांटने की राजनीति का हिस्सा है और यह दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सोची समझी साजिश है।

गोविंदपुरा विधानसभा में रोड शो के दौरान बोले सीएम शिवराज

कांग्रेस के झूठ और छलावे में न आएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार तीसरे दिन भोपाल में रोड शो किया। उन्होंने शुक्रवार को गोविंदपुरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर के समर्थन में जनसंपर्क और सभा की। इस दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री की अगवानी की। सीएम चौहान ने रोड शो की शुरुआत शिवनगर से की और फिर बाग सेवनिया में भी लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क और सभा की।

इस दौरान चौहान के साथ भाजपा की प्रत्याशी और विधायक कृष्णा गौर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान स्थानीय रहवासियों ने सीएम चौहान का मामा... मामा पुकार कर अभिवादन किया और उन पर पुष्प वर्षा की। रोड शो के दौरान कई स्थानों पर सीएम का तिलक कर आरती भी उतारी गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अच्छी सरकार चलाने का काम भाजपा ही कर सकती है। इसलिए सभी लोग कांग्रेस के झूठ और छलावे में न आएं और बीजेपी को सहयोग करें। मैंने सरकार नहीं परिवार चलाने का काम किया है। इसलिए लाड़ली बहना योजना में किसी के साथ कोई जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया।

हम आदिवासी बहनों को चप्पल पहना रहे हैं, तो इनके सीने में काटे चुभ रहे है-सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल । हमारी आदिवासी बहनें जब जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने जाती थीं, तो प्यास से उनका कंठ सूखने लगता था, पैरों में कांटे चुभ जाते थे। जब किसी आदिवासी भाई-बहन के पैरों में कांटा चुभता है, तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभ जाता है। उनकी तकलीफों को देखते हुए हमारी सरकार ने आदिवासी बहनों को चप्पल, पानी की कुप्पी और साड़ी देना शुरू किया था। लेकिन कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार ने यह योजना बंद कर दी थी। अब हमारी सरकार फिर से तेंदूपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को जूते-चप्पल पहना रही है, पानी की कुप्पी और साड़ी दे रही है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है और इसी के चलते वह हमेशा आदिवासियों को अपमानित करती रही है। लेकिन कमलनाथ और प्रियंका जी सुन लें, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी और बहनों की विरोधी बताते हुए कही।

सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों, जनजातीय नायकों को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस केवल अपने नेताओं

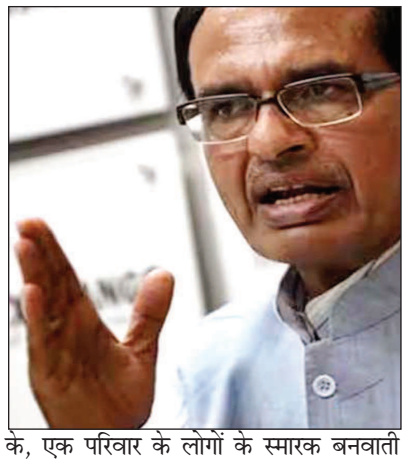

के, एक परिवार के लोगों के स्मारक बनवाती रही, लेकिन कभी भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती को सम्मान नहीं दिया। इनके स्मारक हम बनवा रहे हैं। अपनी आदिवासी विरोधी सोच के चलते कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में कभी शिवभानुसिंह सोलंकी जी और जमनाबाई जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हमारी सरकार बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खातों में 2017 से पोषण अनुदान के 1000 रुपये डालती थी, लेकिन उससे भी इन्हें तकलीफ थी और कमलनाथ की सरकार ने आते ही इन गरीब बहनों के पैसे भी बंद कर दिए। इन्होंने हमारे गरीबों, आदिवासी भाइयों के लिए सहारा बन रही संबल योजना भी बंद कर दी थी। श्री चौहान ने कहा कि वो कांग्रेस ही है, जिसने आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय किया है।

कांग्रेस से सावधान रहें बहनें, इनकी नजर बहनों के पैसों पर है-मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी बहनों के पैसे छीने थे, अब उनकी नजर लाडली बहनों को मिलने वाले पैसों पर है और कांग्रेस के इस लोग इस योजना को बंद कराने की तैयारी कर रहे हैं। इनके लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मामा चुपके से पैसा डालेगा.....। हां, मैं बहनों के खातों में पैसे डालूंगा। ये पहले से चल रही योजना है और इसे कोई बंद नहीं करा सकता। श्री चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाग्य है, उनकी खुशहाली है, जिंदगी है। बहनों के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, तो इससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया । इन्हें जब भी मौका मिला, इन्होंने छीना ही है।

Bollywood Update

इन एक्ट्रेसेस ने क्रिकेटर्स से शादी होते ही बदल डाली अपनी प्रायोरिटी

क्रिकेट और बॉलीवुड का साथ बहुत पुराना है। जहां एमएस धोनी: अनटोल्ड स्टोरी से लेकर 83 तक बॉलीवुड क्रिकेट पर कई बड़ी फिल्में बना चुका है तो वहीं कई अभिनेत्रियां भी क्रिकेट की दुनिया के बादशाहों से ब्याह रचा चुकी हैं। शर्मिला टैगोर से लेकर अनुष्का शर्मा तक ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने क्रिकेटर्स से शादी की है, लेकिन, आज हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, शादी के बाद जिन्होंने अपनी प्रयॉरिटी बदल ली और काम से ज्यादा अपने पति, बच्चे और परिवार पर फोकस कर अब घर संभाल रही हैं।

अथिया शेट्टी

बॉलीवुड अभिनेत्री और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने केएल राहुल से शादी के बाद से किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी हैं।

अनुष्का शर्मा

बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज में से एक अनुष्का शर्मा बेटी वामिका के जन्म के बाद से किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी हैं। उनकी आखिरी फिल्म जीरो थी, अब वह लंबे समय बाद चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी।

हेजल कीच

बॉडीगार्ड फेम हेजल कीच भी युवराज सिंह से शादी के बाद से काम करना छोड़ चुकी हैं।

गीता बसरा

हरभजन सिंह से शादी के बाद से गीता बसरा फिल्मों में काम करना छोड़ चुकी हैं। अभिनेत्री लंबे समय से किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी हैं।

नताशा स्टेनकोविक

मॉडल और एक्ट्रेस नताशा ने हार्दिक पांड्या से शादी की है और इसके बाद से फिल्मों में काम करना छोड़ चुकी हैं।

संगीता बिजलानी

क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी के बाद संगीता बिजलानी ने अपने फिल्मी करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बना-बनाया करियर बर्बाद कर दिया।

परिणीति चोपड़ा को लोगों ने किया ट्रोल

नई नवेली दुल्हन परिणीति चोपड़ा बनी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया और एक बार फिर अपने खूबसूरत लुक के लिए छा गईं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के रैंप वॉक के कई सारे वीडियोज सामने आए हैं, जहां उनके लुक की जमकर तारीफ हो रही है। शादी के बाद यह पहली बार है, जब परिणीति किसी फैशन शो में नजर आई हैं। पेस्टल कलर की साड़ी, गले में हार, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ा पहने एक्ट्रेस ने अपनी अदाओं से सभी का दिल चुरा लिया।

लोगों ने जमकर किया ट्रोल

लेकिन शायद कुछ लोगों को एक्ट्रेस का यह लुक पसंद नहीं आया। वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

एक तरफ जहां कई लोगों के परिणीति के इस लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी यूजर्स हैं जो परिणीति को उनके लुक के लिए ट्रोल कर रहे हैं। किसी एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि ये सिंदूर बस चार दिन का है..। किसी अन्य यूजर ने लिखा कि इनकी शादी को अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और ये इतनी मोटी हो गई है।

बिग बॉस के शो में हिस्सा लेने जा रही हैं मन्नारा चोपड़ा

बिग बॉस 17 का प्रीमियर आज से शुरु होने जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान प्रीमियर का कुछ हिस्सा शूट कर चुके हैं। सेट से सलमान खान की एक फोटो भी काफी वायरल हो रही है। शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई फेमस सेलेब्स से लेकर सोशल मीडिया स्टार तक, बिग बॉस 17 से जुड़े कई नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि, अभी शो के कंटेस्टेंट्स से जुड़ी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाल ही में शो से जुड़ी एक और कंटेस्टेंट की डिटेल्स आई है। यह और कोई नहीं, बल्कि प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स।

मन्नारा चोपड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मन्नारा चोपड़ा को शो के लिए अप्रोच किया गया है। मन्नारा, प्रियंका और परिणीति चोपड़ा की कजन सिस्टर हैं। वह कुछ तेलगू फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 2014 में फिल्म जिन के साथ, उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। मन्नारा का असली नाम बार्बी हांडा हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

सिर्फ एक्सरसाइज नहीं इन शानदार तरीके से रह सकते हैं फिट

जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सरसाइज शरीर को एक्टिव बनती है। लेकिन लोग कई कारणों से एक्सरसाइज करने से बचते हैं, जिनमें कठिनाई, काम से संबंधित तनाव, पसीना, थकान, ऊब, लागत और बहुत कुछ शामिल हैं। वहीं कुछ लोग घंटों जिम में समय बिताते है। वहीं, हम में से कई लोग कम समय के चलते जिम जाना पसंद भी नहीं करते हैं। फिर हमारे मन में सवाल आता हैं कि शरीर को एक्टिव रखने के लिए जिम की जरूरत होती है? घर पर रहकर फिट या एक्टिव नहीं रह सकते हैं? अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो घबराएं नहीं। आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आए है, जिससे बिना जिम जाए कुछ आसान तरीकों से अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं।

स्विमिंग करें

स्विमिंग पूरे शरीर के लिए एक बेहतरीन कसरत है जो जोड़ों के लिए आसान है। इसे इनडोर और आउटडोर पूल में साल भर किया जा सकता है।

डांस करें

फिट रहने के लिए डांस सबसे अच्छा वर्कआउट है, जो हाल में बहुत ट्रेंड में भी आ गया हैं। डांस करने से हार्ट संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं और शरीर में लचीलेपन को बढ़ाता है। डांस में जुम्बा, हिप-हॉप या बैले जैसे विभिन्न रूपों में भाग ले सकते हैं।

पकड़म-पकड़ाई

शायद बचपन का यह गेम आपको आज भी याद हो, जब आप अपने माता-पिता या फिर दोस्तों को कहते होंगे कि जरा मुझे पकड़कर दिखाओ। यह एक ऐसा शब्द है, जिसे बोलते ही आपके पैर इतनी तेजी से भागते हैं, जितनी तेजी से आप सामान्य रूप से नहीं भागते हैं। यह खुद के द्वारा दी गई चुनौती होती है, जिसमें आपको काफी मजा आता है। साथ ही इससे आपका शरीर भी फिट रहता है।

एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियां चढ़ें

अगर आप खुद को फिट रखना चाह रहे हैं, तो लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियां चढ़ें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। साथ ही आपका शरीर एक्टिव रहेगा।

पैदल चलना

अगर आप अपने दोस्त या फिर परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बात कर रहे हैं, तो बैठकर या लेटकर न खड़ें बल्कि चल-चलकर बात करें। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक दिन में कितना चल चुके हैं। यह काफी अच्छी आदत होती है। इससे आपका शरीर एक्टिव भी रहेगा।

शादी के बाद अचानक इस लिए बढ़ जाता है लड़कियों का वजन

अक्सर देखा जाता है कि शादी से पहले लड़किया काफी फिट और स्लिम रहती है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है ये स्लिम ट्रिम लड़कियां तेजी से मोटी होने लग जाती है। लड़कियों में ये बदलाव देखते हुए हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से लड़कियों का वजन इतना बढ़ जाता है। वहीं, पुरुषों के शरीर में शादी के बाद इस तरह के बदलाव कम ही देखने को मिलते हैं। तो फिर आखिर शादी के बाद लड़कियों के साथ ऐसा क्या होता है, जो उनका वजन बढ़ जाता है। आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं।

हार्मोनल चेंज

शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ की वजह से लड़की की इंटरनल बॉडी में कई तरह के चेंज होते हैं। जिसकी वजह लड़कियों के शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलते है और इसी कड़ी वजन बढ़ना भी आता है। वहीं, अगर लड़कियां गर्भनिरोधक दवाओं का इस्तेमाल करती है तो वजन बढ़ने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था की वजह से भी लड़कियों का वजन बढ़ जाता है।

असंतुलित खानपान

शादी के बाद लड़कियों में वजन बढ़ने की एक वजह उनका असंतुलित खानपान भी होता है। अक्सर शादी के लड़कियों को अपने सुसराल वालों के अनुसार ही भोजन खाना पड़ता है। जिसमें वो अपने शरीर और डाइट के अनुसार खाना नहीं खा पाती जिसका सारा असर उनकी बॉडी पर मोटापे की शक्ल में दिखता है।

स्ट्रेस का बढ़ना

लड़कियों को अक्सर शादी के बाद स्ट्रेस का भी सामना करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादी के बाद लड़कियों उनती आजादी नहीं होती जितनी उन्हें शादी से पहले होती है। इस वजह से ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद स्ट्रेस और टेशन में रहती है। स्ट्रेस की वजह से उनकी दिनचर्या में काफी बदलाव होते हैं जिसके कारण उनका वजन बढ़ने लगता है।

प्लास्टिक जितना खतरनाक होता है कागज का कप

यदि आप सोचते हैं कि प्लास्टिक कप में मौजूद जहरीले रसायनों से बचने के लिए पेपर कप एक अच्छा विकल्प है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कॉफी का पेपर कप (पेपर के ढक्कन के साथ) भी प्रकृति में मिलने पर जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, हमें प्लास्टिक और पेपर दोनों कप के इस्तेमाल से बचना चाहिए और वैकल्पिक सामग्रियों से बने कप का उपयोग करना चाहिए।

स्वीडन में गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि डिस्पोजेबल कपों में मौजूद रसायन मच्छरों के लार्वा के विकास को नुकसान पहुंचाते हैं। यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर बेथानी कार्नी अल्मरोथ ने बताया कि हमने पेपर कप और प्लास्टिक कप को कुछ हफ्तों के लिए पानी में छोड़ दिया और देखा कि निक्षालित रसायनों ने लार्वा को कैसे प्रभावित किया। सभी मगों ने मच्छरों के लार्वा के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

फूड पैकेजिंग सामग्री में उपयोग किए जाने वाले कागज को सतह कोटिंग के साथ उपचारित करने की आवश्यकता होती है। यह प्लास्टिक आपके हाथ में मौजूद कॉफी से कागज को बचाता है। आजकल, प्लास्टिक फिल्म अक्सर पॉलीलैक्टाइड एक प्रकार के बायोप्लास्टिक से बनी होती है। बायोप्लास्टिक्स का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय संसाधनों (पीएलए का उत्पादन आमतौर पर मक्का, कसावा या गन्ने से होता है) से किया जाता है, जैसा कि बाजार में 99 प्रतिशत प्लास्टिक के मामले में होता है।

प्लास्टिक से कितना अलग है पीएलए?

पर्यावरण प्रदूषण जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पीएलए को अक्सर बायोडिग्रेडेबल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सही परिस्थितियों में तेल आधारित प्लास्टिक की तुलना में तेजी से टूट सकता है, लेकिन यह अभी भी जहरीला हो सकता है। बायोप्लास्टिक जब पर्यावरण में, पानी में पहुंचते हैं तो प्रभावी ढंग से नहीं टूटते हैं।

टिकट के बाद बोले पटवारी

कांग्रेस के पक्ष में सुनामी

100 प्रतिशत सरकार बनाने का दावा शुक्ला ने कहा-इंदौर 1 में नहीं चलेगा गुंडाराज

इंदौर। कांग्रेस ने रविवार की सुबह इंदौर की 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 3 सीटों को होल्ड किया है। टिकट घोषित होने के बाद राऊ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। कांग्रेस के ही पक्ष में सुनामी है। सौ प्रतिशत कांग्रेस की सरकार बनेगी।

राऊ के विकास को पंख लगेंगे। वहीं इंदौर-1 से प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि ये चुनाव धनबल और जनसेवक का चुनाव है। पितृ पर्वत पर इंदौर-1 विधानसभा की माता-बहनों को बुलाकर लालच दिया जा रहा है

बीजेपी वालों से भी कभी नफरत या घृणा की बात नहीं की-टिकट घोषित होने के बाद राऊ से विधायक और उम्मीदवार जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि राऊ विधानसभा मेरा परिवार है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं। पिछले तीन बार से मैंने विपक्ष में रहकर क्षेत्र के लोगों की सेवा की। विकास किया।

अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे राऊ से फिर प्रत्याशी बनाया है इसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के भरोसे ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मुझसे जो बन सका वो सब कुछ परिवार के लिए मैंने किया है। बीजेपी वालों से भी कभी नफरत या घृणा की बात नहीं की। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। मैं मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है।

माताओं-बहनों को बुलाकर दिया जा रहा लालच-टिकट घोषित होने के बाद संजय शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने मुझ पर भरोसा जताया है इसका मैं आभारी हूं। ये चुनाव एक तरफ धन-बल, गुंडा राज का चुनाव है, तो दूसरी तरफ समाजसेवी, जनसेवक चुनाव लड़ रहा है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उन पर कार्रवाई करना चाहिए।

पितृ पर्वत पर विधानसभा-1 की माताओं-बहनों को बुलाकर लालच दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर पैसा दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां गुडों का राज नहीं चलेगा। मैं जनता के लिए मरने से नहीं डरा तो ये मुझे चुनाव क्या हरवाएंगे।

टिकट के लिए चौकसे ने जताया आभार-इंदौर-2 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार जताया, कहा कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। शाम को 6 बजे से विधानसभा इंदौर-2 में भ्रमण करेंगे। यहीं से चुनावी आगाज होगा। लड्डू मिठाई बांटी जाएगी। जमकर आतिशबाजी होगी।

टिकट के बाद विशाल पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया-देपालपुर सीट से टिकट मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा के परिवारजनों आपके सहयोग से पार्टी ने एक बार फिर मुझे देपालपुर से प्रत्याशी घोषित किया है। आप सभी का आभार और धन्यवाद। बता दें विशाल पटेल देपालपुर से विधायक हैं। पिछली बार उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल को चुनाव हराया था। इस बार भी बीजेपी ने यहां से मनोज पटेल को ही उम्मीदवार बनाया है।

भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है सांवेर-रीना बोरासी ने कहा कि हमारी पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है सभी को धन्यवाद। हमें पूरा-पूरा भरोसा है कि जनता खड़गे जी को किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। मैं कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं हूं। मैं जमीन में काम की हूं।

सांवेर मेरा परिवार है। मैं सांवेर को कोने कोने से जानती हूं। यहां पर रोड समस्या, चिकित्सा समस्या, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के कुछ नेता बीजेपी में चले गए थे लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलने के कारण फिर से घर वापसी करने वाले हैं सब संपर्क में हैं। इस बार हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे।

विजन के साथ करेंगे काम-राजा मंधवानी ने कहा कि हम ऐसे ही चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हमारे पास पूरा विजन है। जनता के बीच में गए हैं जनता के मन में काफी उत्साह है। विधानसभा 4 के सभी वार्डों में विधायक प्रतिनिधि के कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ-साथ सभी वार्डों में स्मार्ट क्लिनिक, स्मार्ट स्कूल खोलेंगे।

आज आप सबको पता है कि सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ियों के हालात क्या हैं। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि विकास के काम करेंगे। जनता समझदार हो चुकी है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं जानता को विश्वास दिलाने में कामयाब हूं कि मैं ही उनके विकास का काम करूंगा।

निजी अस्पतालों से फायर एनओसी की मांग, अपनों पर नहीं दे रहे ध्यान

इंदौर। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इंदौर के निजी अस्पतालों में फायर एनओसी के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके लिए अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपने पीसी सेठी अस्पताल के पास ही स्थायी फायर एनओसी नहीं है। स्थायी एनओसी नहीं मिलने का कारण यह है कि अस्पताल में आपातकालीन निर्गम द्वार नहीं है। ऐसे में यदि अस्पताल में आग लग जाएगी तो कैसे निपटेंगे।

यह सबसे बड़ा सवाल है-उल्लेखनीय है कि पीसी सेठी अस्पताल में प्रतिदिन 200 से ज्यादा मरीज आते हैं। इनमें भी अधिकतर गर्भवती महिलाएं होती हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में फायर लाइन भी नहीं है। बता दें कि कलेक्टर इलैया राजा टी ने अस्पतालों की फायर एनओसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन अपने ही अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब निजी अस्पतालों के लिए फायर एनओसी जरूरी है तो शासकीय अस्पताल को लेकर विभाग और खासकर लाइसेंस शाखा के अधिकारी-कर्मचारी गंभीर क्यों नहीं हैं?

अस्पताल में दिनभर रहती है महिलाओं की भीड़-पीसी सेठी अस्पताल में दिनभर महिलाएं उपचार के लिए आती रहती हैं, इसलिए यहां अधिकतर भीड़ रहती है। इनमें भी अधिकांश गर्भवती महिलाएं होती हैं। डिलीवरी के केस भी यहां अधिक आते हैं। इसके बावजूद फायर फायटिंग की उचित व्यवस्था नहीं होना और स्थायी फायर एनओसी नहीं होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है।

लड़कियों की आवाज में काल कर सैन्यकर्मियों से 40 लाख की ठगी, अन्य लोगों को भी बनाया शिकार

इंदौर। अपराध शाखा ने जिस फर्जी एडवाइजरी फर्म का भंडाफोड़ किया उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। फर्म का संचालक उज्जैन में बैठ कर देशभर में ठगी कर रहा था। आरोपित सैन्य अफसर और कर्मचारियों से लाखों रुपये की ठगी कर चुका है। पुलिस ने उज्जैन से सात लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 14 मोबाइल और लेपटाप जब्त हो गए है।

आरोपित ने बताया कि वह एक काल सेंटर की तरह आफिस चला रहा था। यहां से कर्मचारी और स्वयं लड़कियों की आवाज में बात कर लोगों को ट्रेडिंग का झांसा देते थे। डीसीपी (अपराध) निमिष अग्रवाल के मुताबिक जम्मू में पदस्थ सैन्यकर्मी कैलाशचंद्र सहित लगभग 12 लोगों ने 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बैंक खाते की जांच की और शिव अग्रवाल से पूछताछ की। अग्रवाल की चाय की दुकान है। उन्होंने पूछताछ में बताया कि गोविंद नामक व्यक्ति ने उसके खाते का उपयोग किया है। उसने कहा था कि मां ने उज्जैन में प्लाट का सौदा किया है। एक लाख रुपये जमा करवाने के लिए उसने अग्रवाल का खाता ले लिया था।

अधिक दिखाए जाते थे शेयर के भाव-पुलिस ने उज्जैन में छापा मारा और शुक्रवार रात गोविंद परिहा,कमलेश वर्मा, नितेश मालवीय,धीरज जगदुआ,लोकेश कटारिया औरओमप्रकाश चौधरी गिरफ्तार किया है ।गिरोह का सरगना कमलेश वर्मा है। विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन) से बीसीए पास कमलेश ने ही फर्जी फर्म बनाकर बजाज कैपिटल, स्मार्ट कैपिटल औरएसएमएस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से लोगों से रुपये ऐंठने की साजिश की और निवेश की राशि दो से तीन गुना करने का झांसा देने लगा।

लोग उस पर शक न करें इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवा कर फर्जी एक्सेल शीट बनाता था जिसमें शेयर के भाव काफी ज्यादा दिखाए जाते थे।

संपत्ति की जानकारी जुटा रहे

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक गोविंद का काम खाते उपलब्ध करवाना था। वह परिचितों से झांसेबाजी खाते ले लेता था। निवेशकों से ठगी की राशि दूसरों के खातों में ही जमा करवाई जाती थी। डीसीपी के मुताबिक पुलिस आरोपित कमलेश के बैंक खातों की जांच कर रही है। ठगी की राशि से कितनी संपत्ति अर्जित की इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)